RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 16 AUGUST TO 22 AUGUST 2023 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 08 ■ अंक 48 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

स्वतंत्रता दिवस पर रुपये की आजाद उड़ान
Page 2

अब सरकार का खजाना भरेगी ऑनलाइन गेमिंग
Page 3

आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, रेपो रेट 6.50 पर स्थिर
Page 4

editoria!

तिरंगा और जिम्मेदारी

भारत आज 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. वैसे तो आज की दुनिया में आज हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने कोई ना कोई दिवस मनाने का सिलसिला चल पड़ा है. लेकिन स्वतंत्रता दिवस सबसे अलग है. यह आजादी की लड़ाई के उस इतिहास का अंतिम अध्याय है, जिसे संघर्ष और बलिदान की स्याही से लिखा गया है. वह एक बड़ी लड़ाई थी जिसे हमने जीती और इसलिए हम हर साल मिलकर उस जीत का जश्न मनाते हैं. भारत जैसे विविधता भरे देश में उत्सव तो अनेक होते हैं, मगर 15 अगस्त एक ऐसा दिवस है जिसमें हर भारतवासी एक साथ सम्मिलित होता है. वह इस दिन बस एक भारतीय होता है और उसकी पहचान बस वह तिरंगा होता है जिसे वो फन से हाथों में थामता है. बीता एक साल खास रहा जब भारत ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे साल उत्सव मनाया. इसे आजादी के अमृत महोत्सव का नाम दिया गया. इसी के तहत पिछले वर्ष 'हर घर तिरंगा' नाम से एक अभियान चला. इस साल भी 13 से 15 अगस्त तक यह अभियान चल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर किसी से इस अभियान में हिस्सा लेने का आग्रह किया है. उन्होंने देशवासियों से 'हर घर तिरंगा' की वेबसाइट पर जाकर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर अपलोड करने का आह्वान किया है. साथ ही लोगों से अपने सोशल मीडिया अकाउंटों पर अपनी प्रोफाइल तिरंगा करने की भी अपील की है. प्रधानमंत्री और सरकार की यह ख्वाहिश है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों का समारोह एक सरकारी आयोजन भर ना रह जाए, और इसमें लोगों की भी भागीदारी हो. आज की पीढ़ी को तकनीक के जरिये आजादी के महत्व से जोड़ने का यह एक सराहनीय प्रयास है. यह एक वास्तविकता है कि देश के सामने आज विभिन्न तरह की चुनौतियां हैं. लेकिन चुनौतियां 15 अगस्त 1947 से पहले भी थीं. तब की पीढ़ी ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने को एक चुनौती मानकर संकल्प लिया और आजादी की जंग जीती. वैसे ही, आज की पीढ़ी को भी चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और जिम्मेदारी के जज्बे के साथ बदलाव का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन यह एक ऐसा अहसास है जिसे दूसरों को जबरन समझाने से पहले स्वयं समझना जरूरी है, जो लोग देशभक्ति का प्रदर्शन नहीं करते उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रख अपना कर्तव्य करना चाहिए, हमारा तिरंगा एक ध्वज भर नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसे श्रद्धा और समर्पण के साथ वहन किया जाना चाहिए.

देश में चलेंगी 10,000 नई ई-बसें, 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी

ग्रामीण लोगों के लिए विश्वकर्मा योजना

नई दिल्ली। एजेंसी

पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिये गए हैं। इस बैठक से रेलवे के लिए काफी अच्छी खबर निकल कर आई है। बैठक में रेलवे से जुड़े 7 प्रोजेक्ट को मंजूदी दी गई है। ये प्रोजेक्ट रेल लाइन अपग्रेडेशन और नई रेल लाइन बिछाने से जुड़े हैं। इन प्रोजेक्ट में करीब 20,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में यह जानकारी दी। ठाकुर ने बताया कि पीएम ई बस सेवा को बैठक में मंजूरी मिल गई है। इस पर 57613 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 10 हजार नई इलेक्ट्रिकल बसों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

57,613 करोड़ की पीएम ई बस सेवा

देश भर के 169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड़ के आधार पर चुना जाएगा। देश के अधिकांश शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं विशेष रूप से बसों का अभाव है। इसलिए देश के 100 शहरों में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बस सेवाएं चलाई जाएंगी। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को 50 बसें मिलेंगी। 5 लाख से 20 लाख तक की आबादी वाले शहर के लिए 100 बसें मिलेंगी। वहीं, 20 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों के लिए 150 बसें चलाई जाएंगी। जो राज्य और शहर पुरानी बसों को स्क्रैप कराते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त बसें दी जाएंगी। इसे पीपीपी मोड पर किया जाएगा। प्रति किलोमीटर के आधार पर बसें चलाने के लिए केंद्र सरकार की सहायता मिलेगी और यह सहायता 10 साल तक के लिए मिलेगी। हिल एरिया या नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की राजधानी के लिए 90 फीसदी सहायता केंद्र सरकार देगी। इस योजना से देश में ग्रीन मोबिलिटी को बल मिलेगा।

विश्वकर्मा योजना को मिली मंजूरी

रेल मंत्री ने बताया कि देश के वंचित, गरीब और गावों में रहने वाले लोगों के लिए सरकार काफी कुछ कर रही है। कई वर्ग होते हैं जो परंपरागत कारोबार में लगे हुए होते हैं। जैसे- कुम्हार मिट्टी का काम, लोहार लोहे का काम, सुनार सोने का काम आदि। ये लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस बड़े वर्ग को नया आयाम देने के लिए आज विश्वकर्मा योजना (Vishwakarma scheme) को मंजूरी दी गई है। पिछले बजट में भी इस बारे में घोषणा की गई थी। इस योजना में स्किल बढ़ाने पर जोर होगा। नई तकनीक, नए टूल्स और मार्केटिंग पर फोकस होगा। बेसिक और एडवांस दो तरह के कोर्स होंगे। स्किल लेने के दौरान 500 रुपये प्रति दिन का भत्ता भी होगा। मॉर्डन टूल्स खरीदने के लिए 15 हजार रुपये तक का सपोर्ट मिलेगा। विश्वकर्मा योजना में एक लाख रुपये का लोन भी प्रदान किया जाएगा। इसमें अधिकतम 5 फीसदी की ब्याज दर होगी। इससे लोग अपना बिजनस बढ़ा सकेंगे। इसके बाद 2 लाख रुपये का क्रेडिट सपोर्ट भी मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में कारोबारियों को नए टूल्स, नई स्किल और नया मार्केट सपोर्ट मिलेगा।

32,500 करोड़ रुपये के 7 प्रोजेक्ट हुए अप्रूव

रेलवे से जुड़े 32500 करोड़ रुपये के 7 प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं। ये देश के 9 राज्यों में 35 जिलों को कवर करेंगे। इसकी कुल लंबाई 2339 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य को सीधा फायदा होगा। इस प्रोजेक्ट से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से ज्यादा ट्रेनें चल सकेंगी। गौरखपुर कैंट से वाल्मिकी नगर सिंगल लाइन सेक्शन की डबलिंग का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है और लागत 1269 करोड़ रुपये आएगी। गुंटूर-बीबीनगर सिंगल लाइन सेक्शन की भी डबलिंग होगी। इसकी लंबाई 239 किलोमीटर है और लागत 3238 करोड़ रुपये आएगी। तीसरा प्रोजेक्ट चोपान-चुनार सिंगल लाइन सेक्शन की डबलिंग का है।

इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3 महीने के निचले स्तर पर,जानिए क्या है इसके मायने

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कमजोर प्रदर्शन से जून में देश का इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन 3.7 पर्सेंट के साथ तीन महीने के निचले स्तर पर आ गया। शुक्रवार को National Statistical Office (NSO) की ओर से जारी आंकड़ों से यह बात सामने आई है। Index of Industrial Production (IIP) के संदर्भ में मापी गई फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ जून 2022 में 12.6% रही थी। ऐसा कम आधार प्रभाव के कारण रहा था। घ्ह्र का इससे पिछला निचला स्तर मार्च 2023 में 1.9% था। इसके बाद, यह अप्रैल में बढ़कर 4.5% और मई में 5.3% हो गया। 2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान, IIP ग्रोथ 4.5% रही, जो एक साल पहले इसी अवधि में 12.9% थी। ताजा IIP आंकड़ों के अनुसार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रॉडक्शन जून 2023 में 3.1% बढ़ा, जबकि एक साल पहले यह 12.9% था। जून 2023 में बिजली उत्पादन एक साल पहले के 16.4% की तुलना में 4.2% बढ़ा। इस दौरान खनन उत्पादन में 7.6% की ग्रोथ हुई, जो एक साल पहले की अवधि में 7.8% थी। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के अनुसार, पूंजीगत सामान सेगमेंट इस साल जून में 2.2% की ग्रोथ हुई, जबकि एक साल पहले यह 28.6% थी। महीने के दौरान उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में 6.9% की गिरावट आई, जबकि एक साल पहले की अवधि में इसमें 25.2% का इजाफा हुआ था। उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में एक साल पहले के 2.9% की ग्रोथ की तुलना में 1.2% की बढ़ोतरी हुई। इन्फ्रास्ट्रक्चर/कंस्ट्रक्शन वस्तुओं ने एक साल पहले की समान अवधि में 9.4% की तुलना में 11.3% की ग्रोथ दर्ज की। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में महीने में 5.2% की ग्रोथ दर्ज की गई, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 13.8% थी।

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 5.84 लाख करोड़ रुपये पर

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन चालू वित्त वर्ष में अबतक 17.33% बढ़कर 5.84 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह पूरे साल के बजट अनुमान का 32% है। इनकम टैक्स विभाग ने शुक्रवार को बयान में कहा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 10 अगस्त तक लगातार ग्रोथ जारी है। डायेक्ट टैक्स में पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स शामिल है। मौजूदा वित्त वर्ष में 10 अगस्त तक सालाना आधार पर व्यापक आधार पर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 15.73% बढ़कर 6.53 लाख करोड़ रुपये रहा। अब तक 69,000 करोड़ रुपये का 'रिफंड' जारी किया गया है। यह पिछले साल की समान अवधि में लौटाई गई रकम के मुकाबले 3.73% अधिक है। विभाग ने कहा कि 'रिफंड' को एडजस्ट करने के बाद डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 5.84 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 17.33% अधिक है।

स्वतंत्रता दिवस पर रुपये की आजाद उड़ान

भारत ने पहली बार यूएई को इंडियन करेंसी में किया भुगतान

नई दिल्ली। एजेंसी

भारत जब आजादी का 77वां उत्सव मना रहा है, उस वक्त भारतीय रुपये के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है और भारतीय रुपया, अब इंटरनेशनल बनने की दिशा में निकल चुका है। भारत सरकार ने सोमवार को कहा है, कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार का निपटान शुरू कर दिया है। भारत सरकार के मुताबिक, भारत के शीर्ष रिफाइनर मध्य पूर्वी देश UAE से दस लाख बैरल तेल की खरीद के लिए रुपये में भुगतान कर रहे हैं।

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉर्प ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) को भारतीय करेंसी में भुगतान किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह लेनदेन संयुक्त अरब अमीरात के एक स्वर्ण निर्यातक से भारत में एक खरीदार को लगभग 128.4 मिलियन रुपये ($1.54 मिलियन) में 25 किलोग्राम सोने की बिक्री के बाद हुआ है। रुपया-दिरहम में कारोबारी शुरू भारत ने इसी साल जुलाई में संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहूलियत मिल गई थी। इस समझौते के बाद दोनों ही देशों के डॉलर में लेनदेन का भुगतान करने से आजादी मिल गई, जिससे यूएई के सामानों पर डॉलर का वैल्यू बढ़ने का प्रभाव अब नहीं पड़ेगा।

कारोबार 100 अरब डॉलर के पार

15 जुलाई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गये थे। एमओयू स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS) प्रणाली की शुरुआत करता है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। यह रुपये और दिरहम का उपयोग करके सीमा पार लेनदेन का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध काफी मजबूत हुए हैं और दोनों देशों का लक्ष्य आपसी कारोबार को 100 अरब डॉलर के पार ले जाना है। 2022/23 में भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय व्यापार 84.5 बिलियन डॉलर था, लिहाजा रुपये में कारोबार के शुरू होने से दोनों ही देशों को काफी फायदे होने वाले हैं।

दोनों देशों को होंगे काफी फायदे

दोनों देशों के बीच थ्एए सिस्टम के शुरू होने के बाद सबसे बड़ा फायदा लेनदेन के समय और लागत में कमी है। मध्यस्थ मुद्राओं की आवश्यकता को समाप्त करके, दोनों देश विदेशी मुद्रा खर्चों में बचत की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे आर्थिक सहयोग बढ़ेगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय मुद्राओं पर निर्भरता से आर्थिक लचीलापन बढ़ने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत होने का अनुमान है। सोने के साथ रुपया-दिरहम ट्रेड का कारोबार शुरू होने के बाद अब दोनों देशों के बीच कच्चे तेल का कारोबार भी स्थानीय मुद्रा में शुरू हो गया है, लिहाजा आने वाले समय में, यूएई से जो तेल आता है, उस पर डॉलर का प्रभाव खत्म हो जाएगा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सोना, रत्न और आभूषण सबसे ज्यादा कारोबार होने वाली वस्तुओं में से एक हैं, ऐसे लेनदेन का सफल निष्पादन इस तंत्र की व्यवहार्यता के लिए एक वसीयतनामा के रूप में काम करता है।

देश का निर्यात जुलाई में 16 प्रतिशत कम होकर 32.25 अरब डॉलर पर

व्यापार घाटे में भी कमी

नई दिल्ली। एजेंसी

वैश्विक स्तर पर मांग में नरमी तथा पेट्रोलियम, रत्न और आभूषण एवं अन्य प्रमुख क्षेत्रों के कमजोर प्रदर्शन से देश का कुल निर्यात इस साल जुलाई महीने में 15.88 प्रतिशत घटकर 32.25 अरब डॉलर रहा है। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आलोच्य महीने के दौरान आयात भी 17 प्रतिशत घटकर 52.92 अरब डॉलर रहा, जो बीते वर्ष के जुलाई माह में 63.77 अरब डॉलर था। आयात में कमी से व्यापार घाटा कम होकर 20.67 अरब डॉलर रहा जो एक साल पहले इसी महीने में 25.43 अरब डॉलर था।

आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जुलाई के दौरान निर्यात 14.5 प्रतिशत घटकर 136.22 अरब डॉलर रहा। अप्रैल से जुलाई की अवधि के दौरान आयात 13.79 प्रतिशत घटकर 213.2 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं। अमेरिका और यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों समेत कई देशों के निर्यात और आयात में कमी आई है। इन दोनों क्षेत्रों से आयात लगातार कम हो रहा है।

हालांकि, उन्होंने उम्मीद जतायी कि देश का वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 2023-24 में बीते वित्त वर्ष के 776 अरब डॉलर के मुकाबले अधिक होगा। बर्थवाल ने यह भी कहा कि पिछले दो साल से देश के निर्यात में वृद्धि हो रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस साल के निर्यात आंकड़े को देखना चाहिए।सचिव ने कहा कि जो क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। इसका मतलब है कि भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखला से स्वयं को एकीकृत कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार, सोने का आयात चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में 2.7 प्रतिशत बढ़कर 13.2 अरब डॉलर रहा, जो बीते वित्त वर्ष 2022-23 की अप्रैल-जुलाई में 12.86 अरब डॉलर था। तेल आयात आलोच्य अवधि में 23.4 प्रतिशत घटकर 55 अरब डॉलर रहा जो एक साल पहले इसी अवधि में 71.74 अरब डॉलर था।

BRICS का मेंबर बनना चाहते हैं 23 देश

G-20 से मुकाबले की तैयारी, भारत की भुमिका अहम

नई दिल्ली। एजेंसी

दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में 22-24 अगस्त को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में नये सदस्यों के शामिल किए जाने पर चर्चा होगी। जानकारों का दावा है कि नये सदस्यों के ब्रिक्स में शामिल होने पर यह जियो पालिटिक्स में जी-20 के मुक़ाबले खड़ा हो सकता है। ब्रिक्स (BRICS) मेंबर बनने के लिए दुनिया भर से कुल 23 देशों ने आवेदन किया है। इनके नाम हैं- अल्जीरिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, बोलिविया, वेनेज़ुएला, वियतनाम, होंडूरास, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, क्यूबा, कज़ाखस्तान, कुवैत, मोरक्को, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), फलेस्टाइन, सऊदी अरब, सेनेगल, थाइलैंड और इथोपिया। दुनिया के नक्शे में इन देशों की लोकेशन से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिक्स में अगर ये सभी देश शामिल हुए तो यह संगठन पूरी दुनिया में किस तरह अपना विस्तार हासिल करेगा। वर्तमान समय में ब्रिक्स में कुल पांच देश- ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में 22-24 अगस्त को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में नये सदस्यों के शामिल किए जाने पर चर्चा होगी। जानकारों का दावा है कि नये सदस्यों के ब्रिक्स में शामिल होने पर यह जियो पालिटिक्स में जी-20 के मुक़ाबले खड़ा हो सकता है।

- जी-20 बनाम ब्रिक्स प्लस हुआ तो ...?

ब्रिक्स देशों में इस वक़्त दुनिया की लगभग आधी आबादी रहती है एवं इसके पास दुनिया की एक चौथाई जीडीपी है। नए सदस्यों के बनने के बाद भू-राजनीतिक समीकरण तेज़ी से बदल सकता है। जी-20 में मौजूद रूस और चीन को लगता है कि यह संगठन अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों के एजेंडे को आगे बढ़ाता है। रूस और चीन की मंशा पश्चिमी देशों से अलग एक मज़बूत वैश्विक गठबंधन बनाने की है। ब्रिक्स के विस्तार के बाद ब्रिक्स प्लस का स्वरूप उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मौजूदा समय में जी-20 में अर्जेंटीना, आस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह सबसे अधिक ताकतवर संगठन है। दुनिया के जीडीपी का 85 फ़ीसदी एवं तीन-चौथाई व्यापार और दो-तिहाई आबादी जी-20 में शामिल है। मौजूदा ब्रिक्स के सभी सदस्य जी-20 में शामिल हैं एवं ब्रिक्स के नये सदस्यों में से अर्जेंटीना एवं सऊदी अरब भी जी-20 के सदस्य है।

भारत की होगी अहम भूमिका

भारत ने इस साल एण्ध की अध्यक्षता की थी और अब जी-20 की अध्यक्षता करने जा रहा है। ब्रिक्स हो या जी-20 या फिर एण्ध इन संगठनों में केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो दोनों पक्षों के साथ समान भाव से जुड़ा है। रूस के बाद चीन के साथ भी अमेरिका एवं पश्चिमी देशों का तनाव बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में इन संगठनों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा में भारत की भूमिका अहम साबित होगी। भारत एक मात्र ऐसा देश होगा जो दोनों पक्षों के लिए विश्वसनीय होगा। भारत की आर्थिक मज़बूती एवं विभिन्न वैश्विक मंचों पर ज़ोरदार उपस्थिति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत के लिए एक सुनहरा मौक़ा लेकर आने वाली है। विभिन्न संगठनों के बीच संवाद एवं संतुलन क़ायम करने में भारत एक प्रभावी भूमिका अदा कर सकता है।

अब सरकार का खजाना भरेगी ऑनलाइन गेमिंग

नए कानून के बाद आएंगे 45-50 हजार करोड़

नई दिल्ली। एजेंसी

ऑनलाइन गेम पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी वसूलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। नई व्यवस्था के अमल में आने से जहां ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीनों को तगड़ा झटका लगने वाला है, वहीं सरकारी खजाने को मोटा फायदा होना वाला है। ऐसा अनुमान है कि ऑनलाइन गेमिंग पर अप्रत्यक्ष कर की दरें बढ़ने से सरकार को अतिरिक्त 45-50 हजार करोड़ रुपये मिल सकते हैं।

संसद से मंजूर हो चुका है बिल

नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के बारे में कोई निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेम पर 28 फीसदी की दर से टैक्स वसूलने का प्रस्ताव दिया था। उसके लिए कानून में जरूरी संशोधन को मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक को संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया गया था। संसद में संबंधित दो विधेयकों को मंजूर किया जा चुका है। जल्दी ही नया कानून अमल में आ जाएगा, जिससे ऑनलाइन गेम के शौकीनों को पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, जबकि सरकार को मोटी कमाई होगी।

डीजीजीआई के अधिकारियों की राय

एक हालिया खबर में डाइरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटलीजेंस यानी डीजीजीआई के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगने पर सरकार को 50 हजार करोड़ रुपये तक की कमाई हो सकती है। अधिकारियों के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने अपने रेवेन्यू पर 18 फीसदी की दर से टैक्स दिया होगा, लेकिन अब उन्हें 2017 से अब तक रेवेन्यू पर 28 फीसदी के हिसाब से टैक्स देना होगा।

2017 से ही होगा कैलकुलेशन

नए कानूनों के अमल में आने के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर देनदारी का कैलुलेशन 2017 से ही किया जाएगा, जब नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी जीएसटी लागू हुई थी। डीजीजीआई के अधिकारियों का कहना है कि 2017 से अब तक का कैलकुलेशन करने पर यह हिसाब 45 से 50 हजार करोड़ रुपये का बैठेगा। उनके अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से सरकार को अब अतिरिक्त 45-50 हजार करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकता है।

इन मामलों में देना होगा ज्यादा टैक्स

जीएसटी काउंसिल (उएऊ ण्दल्हम्त) ने हाल ही में हुई अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेम, कसीनो और हॉर्स-रेसिंग यानी घुड़-दौड़ पर टैक्स की दरें बदलने के बारे में निर्णय लिया था। अब ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स-रेसिंग पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी GST लगेगा। यह टैक्स दांव (Bet) पर लगाई जानी वाली पूरी रकम पर लगेगा। इसी तरह, कसीनो के मामले में खरीदे गए चिप की वैल्यू पर टैक्स लगेगा। यह टैक्स ऑनलाइन गेम खिलाने वाली कंपनियों को भरना होगा।

न्यूयॉर्क सबसे महंगा और ढाका सबसे सस्ता शहर

मुंबई देश में सबसे महंगा, सूची में 351 नंबर पर

नई दिल्ली। एजेंसी

एजेंसी क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मकान का सबसे ज्यादा किराया कहां हैं? इसका जवाब है न्यूयॉर्क। अमेरिका के इस शहर में वन बेडरूम अपार्टमेंट का मंथली रेंट 3,789 डॉलर है। इंडियन करेंसी में देखें तो न्यूयॉर्क का यह किराया 3,14,322 रुपये बैठता है। इस लिस्ट में सिंगापुर दूसरे नंबर पर है। इस एशियाई देश में आपको सिटी सेंटर में एक बेडरूम 3,454 डॉलर के मंथली रेंट पर मिल जाएगा। रेंट के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 मंहगे शहरों की बात करें तो इनमें सात अमेरिका के हैं। इनमें न्यूयॉर्क के अलावा सैन फ्रांसिस्को, ब्रुकलिन, बोस्टन, सैन डिएगो, मियामी और सैन होजे शामिल हैं। टॉप 10 में इसके अलावा बरमूडा के हैमिल्टन और जर्मनी के ज्यूरिख को जगह मिली है।

World of Statistics के मुताबिक दुनिया के 13 शहरों में वन बेडरूम अपार्टमेंट का मंथली रेंट 2,500 डॉलर से ज्यादा है। इनमें जॉर्ज टाउन, लॉस एंजिलिस और लंदन शामिल हैं। लंदन के सिटी सेंटर में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का मंथली रेंट 2,614 डॉलर है। भारतीय मुद्रा में यह राशि करीब 2,16,848 रुपये बैठती है। हॉन्ग कॉन्ग में यह 2,274 डॉलर, डबलिन में 2,121 डॉलर, सिडनी में 2,114 डॉलर, दुबई में 1,976 डॉलर, पेरिस में 1,411 डॉलर, टोक्यो में 974 डॉलर और शंघाई में 930 डॉलर है।

दिल्ली-मुंबई का हाल

जहां तक भारत का सवाल है तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का एक महीने का किराया 570 डॉलर यानी 47,285 रुपये है। मुंबई रेंट के हिसाब से देश का सबसे महंगा शहर है लेकिन दुनिया में इसकी रैंकिंग 351वीं है। दिल्ली में वन बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट मुंबई की तुलना में आधे से भी कम है। दिल्ली में आपको 245 डॉलर यानी 20,324 रुपये के मंथली रेंट पर एक बेडरूम का अपार्टमेंट मिल जाएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और बांग्लादेश की ढाका में मंथली रेंट सबसे कम है। इस्लामाबाद में यह 152 डॉलर और ढाका में 135 डॉलर है।

होम लोन पर मिलेगी बंपर सब्सिडी, सरकार ला रही स्कीम

नई दिल्ली। एजेंसी

गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का घर का सपना पूरा करने के लिए पीएम ने मंगलवार को एक अहम घोषणा की। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार होम लोन पर ब्याज में राहत देने के लिए एक योजना लेकर आ रही है। जल्दी ही इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम की घोषणा की जा सकती है। इससे शहरों में झुग्गी-झोपड़ी और किराए पर रहने वाले लोगों का अपने घर का सपना पूरा हो सकेगा। इससे उन लोगों को फायदा होगा जो पीएम आवास योजना (PMAY) का लाभ नहीं उठा सके हैं। हाल में होम लोन काफी बढ़ गया है। इसकी वजह यह है कि आरबीआई ने पिछले साल मई से रेपो रेट में 2.5 परसेंट की बढ़ोतरी की है।

मोदी ने कहा, 'शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं। मध्यम वर्ग के परिवार जो अपने घर का सपना देख रहे हैं, हम आने वाले कुछ सालों में उनके लिए योजना लेकर आ रहे हैं। जो शहरों में रहते हैं, किराए के मकान, झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, चॉल में रहते हैं, ऐसे लोगों को जो लोन मिलेगा, उसके ब्याज में लाखों की राहत देने का फैसला किया है।' देश में अब भी एक बड़ी आबादी झुग्गियों में रहती है। आरबीआई ने पिछले साल मई से रेपो रेट में 2.5 परसेंट की बढ़ोतरी की है। इससे होम लोन समेत सभी तरह के लोन महंगे हो गए हैं। हालांकि तीन बार से आरबीआई ने रेपो रेट को यथावत रखा है।

क्या हो सकती है यह स्कीम

शहरी इलाकों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र झुग्गी के रिडेवलपमेंट के एक लाख रुपये और पार्टनरशिप में सस्ता मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपये मिलते हैं। साथ ही इसमें लाभार्थी के नेतृत्व वाली निर्माण योजना यानी बीएलसी (Beneficiary led individual construction or enhancement) वर्टिकल्स भी है। इसके साथ ही क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (ण्थ्एए) वर्टिकल भी थी। इसमें लोगों को घर खरीदने पर 2.7 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलती थी। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इसका फायदा मिलता था लेकिन यह स्कीम मार्च 2022 में खत्म हो गई।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि नई स्कीम सीएलएसएस कैटगरी में शुरू की जा सकती है। इसमें देश में बेहतर क्वालिटी के मकानों के साथ-साथ सस्ते मकानों को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी तेजी आएगी। इस सेक्टर में तेजी आने से देश में रोजगार बढ़ेगा। साथ ही सीमेंट और स्टील की खपत भी बढ़ेगी। देश में अब भी एक बड़ी आबादी झुग्गियों में रहती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक शहरों में 17 फीसदी आबादी झुग्गियों में रहती है। साथ ही किराए पर रहने वाले लोगों का भी घर लेने का सपना इस स्कीम से पूरा हो सकेगा।

आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, रेपो रेट 6.50 पर स्थिर

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद नीतिगत निर्णय की घोषणा कर दी गई है। आरबीआई ने एमपीसी की बैठक के बाद एक बार फिर रेपो रेट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आरबीआई ने गुरुवार को लोगों को बड़ी राहत देते हुए रेपो रेट को स्थिर रखा है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी रेपो रेट 6.50 फीसदी पर बरकरार है। जैसा की पहले से अनुमान लगाया जा रहा था आरबीआई ने रेपो रेट को स्थिर रख सकता है, ऐलान भी उसी तरह से हुआ है।

8 अगस्त से शुरू हुई थी बैठक

बता दें कि आरबीआई की मॉनीटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक आठ अगस्त को शुरू हुई थी। यह बैठक 10 अगस्त तक चली। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikant Das) ने इसमें लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी है। हाल में देश में खानेपीने की चीजों के दामों में काफी तेजी आई है। माना जा रहा है था कि महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई लगातार तीसरी बार नीतिगत दरों को यथावत रख सकता है।

पहले से लगाया जा रहा था अनुमान

ब्लूमबर्ग के एक सर्वे में सभी 42 इकनॉमिस्ट्स ने भी इस बात का अनुमान लगाया था कि आरबीआई की छह सदस्यीय एमपीसी रेपो रेट को 6.50 परसेंट पर बनाए रख सकती है। बता दें कि जून में खुदरा महंगाई 4.81 परसेंट रही जो इसका तीन महीने का उच्चतम स्तर है। हाल में चावल और गेहूं के साथ-साथ सब्जियों की कीमत में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। माना जा रहा है कि जुलाई में महंगाई की दर आरबीआई के टारगेट रेंज से ऊपर पहुंच गई है।

नहीं मिली राहत

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है। इससे ऐसे लोगों को राहत नहीं मिली है जो ईएमआई में राहत की उम्मीद लगाए हुए थे। बता दें कि पिछले साल मई से रेपो रेट में 2.5 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। इससे सभी तरह के लोन महंगे हो गए हैं। लोग काफी समय से लोन सस्ता होने की उम्मीद लगाए हुए थे। लेकिन फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिली है। आरबीआई ने देश में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए मई 2022 के बाद से रेपो रेट को कई बार बढ़ाया है। इसके चलते नीतिगत दर रेपो फरवरी 2023 में 6.5 फीसदी पर पहुंच गई थी। इसके बाद आरबीआई ने अप्रैल और जून में इसे यथावत रखा था।

RBI ने तो ब्याज दर नहीं बढ़ाई, फिर क्यों महंगे हो रहे हैं लोन?

नई दिल्ली। एजेंसी

रिजर्व बैंक ने रीपो रेट को 6.50 प्रतिशत पर बरकरार रखते बैंकों के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन शुक्रवार को कई सरकारी बैंकों ने अपनी लेंडिंग रेट बढ़ा दी। बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB), केनरा बैंक, बैंक ऑफ महराष्ट्रा ने श्ण्ढ्ढ लोन दर में 0.10 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। बैंकों के इस कदम से श्ण्ढ्ढ से जुड़ी मासिक किस्त (EMI) बढ़ जाएगी।

MMW फाइनेंशल सर्विसेज के फाइनेंस मेंटॉर विशेष गांधी कहते हैं, 'बैंक ग्राहकों को न तो इस बारे में बताते है कि रेट में बढ़ोतरी का उनके EMI पर क्या असर होगा और न ही उन्हें लोन रिसेट करने का ऑप्शन देते हैं। जब भी रेट बढ़ते हैं ग्राहकों से कम्यूनिकेट किए बिना उनका टेन्योर इतना बढ़ाते जाते हैं कि उसे चुकाने में वर्षों लग जाते हैं। ऐसे में आरबीआई की टेन्योर को रिसेट करने की गाइडलाइन आने के बाद कस्टमर्स के लिए बहुत राहत भरा कदम होगी।' गांधी का कहना है कि इस समय सप्लाई चैन की समस्या है और डिमांड काफी है। ऐसे में अतिरिक्त नगदी को सिस्टम से निकालने व महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए बैंक लोन की दर को बढ़ा रहे हैं। किस पर होगा असर हालांकि विभिन्न बैंकों द्वारा MCLR बढ़ोतरी किए जाने से केवल वे ग्राहक प्रभावित होंगे, जिनकी ब्याज दरें MCLR पर आधारित हैं। दरअसल 1 अक्टूबर 2019 से बैंकों को अपने लोन पर ब्याज दरों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ना की छूट दी गई है, इसलिए रीपो रेट बेस्ड लोन लेने वाले ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं होगा, यानी उनकी लोन की श्ंढ्ढ नहीं बढ़ेगी।

होम लोन की EMI कैसे घट सकती है, कस्टमर को बताइए... RBI ने बैंकों से क्या-क्या कहा

नई दिल्ली। एजेंसी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने कल मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद रेपो रेट (Repo Rate) को लेकर बड़ा ऐलान किया था। आरबीआई ने गुरुवार को लोगों को बड़ी राहत देते हुए रेपो रेट को स्थिर रखा है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी रेपो रेट 6.50 फीसदी पर बरकरार है। हालांकि आरबीआई होम लोन के टेन्योर को लंबे समय तक बढ़ाए जाने से चिंतित है। डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने इस बारे में कहा कि बिना जरूरी लोन के लंबे टेन्योर से बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कर्ज भुगतान की अवधि बढ़ाने का मामला अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है। बैंकों को ऐसे मामलों को देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बैंक कस्टमर को यह भी बताएं कि किस तरह से लोन की ईएमआई किस तरह से कम हो सकती है। इससे लोगों को लोन के बोझ से राहत मिल सकेगी।

बैंकों के सीईओ से की चर्चा

उन्होंने कहा, 'यह बैंक बोर्ड को व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की अवधि और प्री पेमेंट की क्षमता को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना है।' एम राजेश्वर राव ने कहा कि ''हमने पहले ही बैंकों के सीईओ के साथ इस पर चर्चा की है और अपनी चिंताओं के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि आरबीआई जल्द ही इसपर विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा। एक रिटायर्ड बैंकर के मुताबिक, टेन्योर को बढ़ाए जाने से मौद्रिक नीति के फैसलों का असर कम हो जाता है। कस्टमर को परेशानी नहीं होती है। इसकी वजह यह है कि लोन लेने वालों को बढ़ती हुई दरों का दबाव तुरंत महसूस नहीं होता है। ऐसे में जबकि होम लोन लेने वालों की संख्या काफी ज्यादा है।

फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा

बैंकरों के मुताबिक, टेन्योर को बढ़ाना हमेशा चिंता का कारण नहीं होता है, क्योंकि ब्याज की दरें एक सर्कल के क्रम में बदलती हैं। अगर आरबीआई दो साल में दरों में कटौती करता है, तो लोन मूल टेन्योर में वापस आ जाएगा। इधर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद कहा कि लोगों के अपनी सुविधानुसार फ्लोटिंग या फिक्स्ड ब्याज दर में से अपनी सुविधानुसार ऑप्शन में चुनाव के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। इसके तहत ऋणदाताओं को ग्राहकों को कर्ज अवधि और ईएमआई के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी। फ्लोटिंग से निश्चित ब्याज दर का विकल्प चुनने या कर्ज समय से पहले खत्म करने का विकल्प देने के साथ लगने वाले शुल्क की जानकारी भी स्पष्ट रूप से देनी होगी।

बदल गए UPI से जुड़े नियम, ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ी, जल्द मिलेगी ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा

नई दिल्ली। एजेंसी

आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक (RBI MPC Meeting) में यूपीआई से जुड़े भी बड़े फैसले लिये गए हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपने स्टेटमेंट में इस बारे में जानकारी दी। आरबीआई ने यूपीआई लाइट पर ट्रांजेक्शन लिमिट को बढ़ा दिया गया है। वहीं, जल्द ही ऑफलाइन पेमेंट्स की सुविधा भी लायी जाएगी। आरबीआई गवर्नर ने यूपीआई पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें यूपीआई लाइट पर ट्राजेक्शन लिमिट को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करना भी शामिल है। दास ने यह भी कहा कि जल्द ही यूपीआई के जरिए ऑफलाइन पेमेंट्स की सुविधा को भी लाया जाएगा। साथ ही यूपीआई प्लेटफॉर्म पर कन्वर्सेशनल पेमेट्स की सुविधा भी शुरू की जाएगी।

बढ़ी ट्रांजेक्शन लिमिट

इस तरह आरबीआई की इस एमपीसी बैठक में यूपीआई से जुड़ी तीन घोषणाएं हुई हैं। पहला यूपीआई पर कन्वर्सेशनल पेमेंट्स की सुविधा लायी जाएगी। यूपीआई पर ऑफलाइन पेमेंट्स की सुविधा होगी। तीसरी- यूपीआई लाइट पर ट्रांजेक्शन लिमिट को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है।

इस साल महंगाई दर के 5.4 फीसदी पर रहने का अनुमान

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि साल 2023-24 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति यानी खुदरा महंगाई दर के 5.4 फीसदी पर रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में खुदरा महंगाई के 6.2 फीसदी, तीसरी तिमाही में 5.7 फीसदी, चौथी तिमाही में 5.2 फीसदी और वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 5.2 फीसदी रहने का अनुमान है।

600 अरब डॉलर के पार गया विदेशी मुद्रा भंडार

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय रुपया जनवरी, 2023 से स्टेबल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर के पार चला गया है।

गुलाम मानसिकता और देशभक्ति के बीच उलझा समाज

राजकुमार जैन
स्वतंत्र विचारक एवं विचारक

इतिहास गवाह है कि गुलामी का जीवन जी रहे एक परतंत्र देश के नागरिकों के मन में देशभक्ति की भावना अपने चरम पर होती है। गुलामी के उस दौर में सभी नागरिकों का एकमात्र लक्ष्य अपने देश को स्वतंत्र करवाना होता है और स्वतंत्रता के उस संघर्ष में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना यहाँ तक कि प्राणों का उत्सर्ग कर देना भी गौरव की बात मानी जाती है। लेकिन स्वतन्त्रता मिल जाने के बाद संघर्ष के आदी हो चुके उन्हीं देशभक्त नागरिकों के समक्ष यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि एक स्वतंत्र देश के नागरिक के रूप में किससे संघर्ष करना है। वो समझ नहीं पाते कि अब उनके लिए देशभक्ति के मायने क्या है। यह सच है कि देशभक्ति की भावना कभी मरती नही है लेकिन उचित मार्गदर्शन या स्पष्ट उद्देश्य के अभाव में वह सुप्तावस्था में चली जाती है।

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने की खुशियाँ तो बहुत मनाई गई लेकिन तत्कालीन नेतृत्व या किसी और ने यह नहीं सोचा कि अब क्या। आज हम पाते हैं कि परतंत्र से स्वतंत्र होने पर सत्ता का सिर्फ नाम बदला है। वो राजतन्त्र से लोकतंत्र तो हो गया, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। वो तो वही बनी हुई है कि एक राजा होता है, उसका मंत्रिमंडल होता है, कुछ सलाहकार होते हैं, कुछ चाटुकार होते हैं और होते हैं सत्ता के मद में अंधे कारिंदे जो जनता पर अत्याचार करना अपना अधिकार समझते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि राजा से लेकर अंतिम स्तर के कारिंदे तक सब हमारे अपने ही लोग होते हैं जो कल तक हमारी ही तरह एक आम आदमी हुआ करते थे। लेकिन कुर्सी पर आसीन होते ही वो स्वयं को अलग समझने लगते हैं। सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों हो जाता है, गड़बड़ कहाँ है। कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिये था, व्यवस्था बदलनी चाहिए थी, लोगों की मानसिकता को सही दिशा देने का काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ या हुआ भी तो पूरी तरह से नहीं हुआ।

राष्ट्र निर्माण में एक आम नागरिक के योगदान के बारे में किसी स्पष्ट उद्देश्य और दिशा निर्देश के अभाव में एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में देश भक्ति के बारे में हमारा रवैया कर्म से परे जाकर दिखावटी रूप में पाकिस्तान को क्रिकेट में हराने, चीनी सामान का बहिष्कार करने, इंग्लैंड से हमारा पुराना सामान वापस लाने, पाकिस्तान युद्ध पर बनी फिल्म देखकर तालियां बजाने, राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान गाते समय खड़े होने तक ही सिमट कर रह गया। एक आम नागरिक इससे या इसी तरह की अन्य बातों से परे जाकर देशभक्ति के बारे में और अधिक चिंतन और मनन नहीं कर पाता है ।

इस सब के बावजूद भी एक बात तो है जो हमें महान बनाती है कि जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भाषा, भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक झुकाव, आदि अनेकों प्रकार के विभिन्न छोटे-छोटे हिस्सो में बंटे हम भारतीय जब भी देशभक्ति की बात आती है तो ना जाने कैसे हम सब एक हो जाते है। सारे मतभेद और मानभेद भुलाकर बस 'भारतीय' हो जाते हैं। यह चमत्कार कैसे होता है यह कोई नही जानता। यह एक अद्भुत बात है कि देश का प्रत्येक नागरिक देशभक्त कहलाना पसंद करता है और देशद्रोही कहलाने की बजाय जीवन त्याग करना पसन्द करता है ।

आज जरूरत है देशभक्ति की इसी प्रबल भावना को एक सही दिशा देने की। जरूरत है लोगों को यह शिक्षा देने की और समझाने की एक सच्चा देशभक्त नागरिक अपने देश को एक महान देश बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। वो देश के प्रति समर्पित, साहसी और मजबूत इरादों वाला होता है । प्रत्येक नागरिक निरंतर राष्ट्र निर्माण की भावना को स्थायी रूप से अपनाए यह एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। हमें यह अनुभूति होनी चाहिए कि 'मैं ही राष्ट्र निर्माण के लिए उपयुक्त व्यक्ति हूं'। मेरे द्वारा सम्पन्न किया गया प्रत्येक कार्य राष्ट्र निर्माण में सहयोगी होना चाहिए।

नेतृत्व को देशवासियों के मन में यह भाव भरने का कार्य करना होगा कि केवल सेना या पोलिस में या अन्य सुरक्षा एजेंसियों में काम करते देश के दुश्मनों से संघर्ष करते हुए शहीद हो जाना ही देशभक्ति नहीं है। देशप्रेम प्रकट करने के लिए सैनिक बनना ही एकमात्र उपाय नही है। हर कोई सैनिक नही बन नही सकता लेकिन प्रत्येक नागरिक देशभक्त बन सकता है। एक आजाद और सशक्त देश के नागरिकों के लिए देशभक्ति के मायने क्या होना चाहिए इसके लिए एक विस्तृत सोच विचार की आवश्यकता है।

वस्तुतः नागरिकों का एक दूसरे के प्रति सदव्यवहार भी देशभक्ति है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं सांप्रदायिक सौहार्द का भाव रखना भी देशभक्ति है। उन्नत नागरिक ही उन्नत देश का निर्माण करते हैं और नागरिकों का उत्थान ही देश का उत्थान है अतः एक दूसरे के उत्थान में मदद करना भी देशभक्ति है। देश का हर नागरिक वो जहां भी हो, जो भी दायित्व उसके पास हो वो अपना अपना कार्य पूर्ण सामर्थ्य और ईमानदारी से अन्य नागरिकों की बेहतरी का भाव रखकर करे यह भी देशभक्ति है । हम हर वो कार्य करें जिससे देश की उन्नति हो यह देशभक्ति है। देश के अंदरूनी विवाद व देश के नागरिकों का आपस में लड़ना, गृह कलह आदि देश के विकास में बाधा खड़ी करते हैं, देश को कमजोर करते हैं। किसी देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए उस देश की एकता और अखंडता अति महत्वपूर्ण है। कोई भी देश तभी उन्नति कर पाता है जब उस देश के नागरिक एकजुट होकर एक सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हों। एकता के सूत्र में बंधे ऐसे मजबूत देश को सम्पूर्ण विश्व सम्मान की दृष्टि से देखता है। हमें अपने कर्मों और व्यवहार से और उच्च स्तरीय नागरिक बोध से भारत को विश्व का सिरमौर बनाकर दुनिया के शीर्ष पर स्थापित करना है। जय भारत।

शेंगेन वीजा के लिए वेटिंग पीरियड घटा

नई दिल्ली। एजेंसी

यूरोप, खास कर जर्मनी जाने वालों के लिए आसानी हो गई है। यूरोप जाने में इस्तेमाल होने वाले 'शेंगेन वीजा' प्राप्त करने से संबंधित कार्यवाही की अवधि अब घटा कर आठ सप्ताह कर दी गई है। यह जानकारी दिल्ली में जर्मन दूतावास के उप प्रमुख जॉर्ज इंजविलर ने बुधवार दी। उन्होंने बताया कि जर्मनी की यात्रा करने के लिए 'शेंगेन वीजा' से संबंधित कार्यवाही अवधि घटाकर आठ सप्ताह कर दी गई है। इसे और कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

और बेहतरी का प्रयास

इंजविलर ने यहां संवाददाता से बातचीत में कहा, ''वीजा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम आवेदन के समय को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बात ऐसी है कि हम इसे आज से कल तक बदलना चाहेंगे। हम विभिन्न माध्यमों से काम कर रहे हैं। हमने मुंबई में अपने कर्मी बढ़ा दिए हैं और मैं समझता हूं कि प्रतीक्षा अवधि बहुत कम हो गई है।''

इंतजार अवधि घटी

इंजविलर ने एक सवाल के जवाब में कहा, ''अब हम करीब आठ हफ्ते पर आ गए हैं। हमें और अच्छा होने की उम्मीद है क्योंकि यही हम भी चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जर्मनी में भारतीयों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम आपको यहां बुलाकर आपसे कहें कि वीजा के लिए तीन साल पहले आवेदन करें और तब ही आपको अच्छा मौका मिलेगा।''

क्या है शेंगेन वीजा

'शेंगेन वीजा' लघु अवधि ठहराव (90 दिन तक) का वीजा है जो व्यक्ति को पर्यटन या कारोबारी उद्देश्य के लिए यूरोप के 27 देशों के शेंगेन क्षेत्र के किसी भी सदस्य देश में यात्रा की अनुमति देता है। इस समय भारत में अमेरिका और कनाडा के साथ साथ यूरोपीय देशों के लिए वीजा का वेटिंग पीरियड काफी बढ़ गया है। ऐसे में जर्मन दूतावास की घोषणा से भारतीयों को सहूलियत होगी। वैसे भी, वीजा आवेदन पर कार्यवाही में देरी से यूरोप यात्रा के प्रति लोगों में उत्साह कम देखा जा रहा है।

जर्मनी में बढ़ी भारतीय पर्यटकों की संख्या

भारत के लिए जर्मनी राष्ट्रीय पर्यटक कार्यालय (जीएनटीओ) के निदेशक रोमित थियोफिलस ने बताया कि भारतीय पर्यटकों ने 2022 में जर्मनी में 6.23 लाख से अधिक रातें बिताईं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 209 प्रतिशत अधिक है। जर्मनी के राष्ट्रीय पर्यटक बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, ये आंकड़ा कोविड-19 महामारी से पूर्व की तुलना का अब भी सिर्फ 65 प्रतिशत ही है। भारतीयों ने जर्मनी में साल 2021 के दौरान वहां 2.01 लाख रातें बिताईं थी।

इससे पहले 2019 में गए थे इतना

थियोफिलस ने कहा, ''भारतीयों ने 2019 में जर्मनी में रिकॉर्ड 9.61 लाख से अधिक रातें बिताईं थी। उक्त आंकड़ा 2019 के मुकाबले 65 प्रतिशत है। इसमें निरंतर वृद्धि की गुंजाइश बनी हुई है। भारतीयों के बीच अंतरराष्ट्रीय यात्रा की भारी मांग है।'' उन्होंने बताया कि जर्मनी एक आकर्षक डेस्टिनेशन है और वहां करने को बहुत कुछ है।

पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 290 रुपये लीटर के पार...

एजेंसी

पाकिस्तान में आर्थिक संकट अपने चरम पर है। पाकिस्तानी मीडिया में वहां के लोग अपनी परेशानी बताते आए दिन दिख जाते जाते हैं। आर्थिक संकट का प्रकोप इतना है कि खाने पीने से लेकर हर वस्तु की कीमत आसमान छू रही है। इसी बीच इस महीने में दूसरी बार पेट्रोल -डीजल (Petrol-Diesel) की कीमत में बढोतरी की खबर सामने आ रही है। इससे पाकिस्तानियों की परेशानी और भी बढ़ जाएगी। मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने ट्वीट के माध्यम से बढोतरी की जानकारी दी है। 16 अगस्त से पेट्रोल को कीमत में 17.50 बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल को कीमत प्रति लीटर 290.45 हो गई है। वहीं डीजल में 20 रूपये बढ़ोतरी के बाद 293.40 रुपये ($1.01) प्रति लीटर हो गई। मालूम हो कि इस महीने की शुरुआत में देश ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ समझौते में तय राजकोषीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की थी, जिससे महंगाई आसमान छू गई थी। कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली भंग हो चुकी है और देश के कार्यवाहक पीएम अनवर-अल-हक कक्कड़ ने सोमवार को ही पद की शपथ ली है। वह अगले चुनाव तक इस पद पर बने रहेंगे। तेल के मोर्चे पर ही पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। उसे रूसी कच्चे तेल का आयात बंद करना पड़ा है। पाकिस्तान सरकार ने अपने फैसले के लिए रूसी कच्चे तेल की गुणवत्ता को जिम्मेदार ठहराया है। द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, पाकिस्तानी रिफाइनरियों ने रूसी तेल को प्रोसेस करने से इनकार कर दिया है। 11 और 26 जून को रूस से दो कच्चे तेल के जहाज कराची बंदरगाह पर पहुंचे, जिसके बाद कोई भी रूसी तेल जहाज पाकिस्तान नहीं पहुंचा।

घर में डस्टबिन किस दिशा में रखना चाहिए, जानिए क्या कहता है वास्तु शास्त्र

वास्तु शास्त्र में घर से जुड़े कई नियमों का जिक्र है। यदि इन नियमों का पालन किया जाए को घर के लोगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर हम घर में कोई वस्तु गलत दिशा में रखते हैं तो इसके नकारात्मक प्रभाव सामने आने लगते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर हम घर में गलत दिशा में कूड़ादान रखते हैं तो मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। आइए जानते हैं घर में डस्टबिन किस दिशा में रखना चाहिए।

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

इस दिशा में न रखें डस्टबिन

■वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में डस्टबिन को उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप इस दिशा में रखते हैं तो इसका असर घर के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है।

■वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि यदि घर में कूड़ेदान को दक्षिण-पूर्व दिशा में रखते हैं तो आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

■वास्तु शास्त्र कहता है कि घर में पूर्व या उत्तर दिशा में डस्टबिन नहीं रखना चाहिए। इससे घर में अवसाद और आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं।

■डस्टबिन को बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। दरअसल, कचरा आपके मन में आने वाले बुरे विचारों का कारण बन सकता है। डस्टबिन कितना भी साफ हो ये नकारात्मक प्रभाव डालता है।

■अगर किसी कपल के बेडरूम में डस्टबिन रखा है तो इसका असर रिश्ते पर पड़ सकता है।

घर में डस्टबिन कहां रखना चाहिए

वास्तु शास्त्र में घर में कूड़ादान रखने की सही दिशा बताई गई है। कूड़ेदान को उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। वहीं, डस्टबिन को कभी भी घर के बाहर नहीं बल्कि अंदर रखना चाहिए।

घर में रखे कूड़ादान का रंग हल्का होना चाहिए। डार्क रंग के डस्टबिन अशुभ होते हैं और वास्तु दोष पैदा करते हैं।

हाथ में कलावा बांधते या उतारते वक्त ध्यान रखें ये बातें, वरना तबाह हो जाएगा पूरा परिवार

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
इंदौर (म.प्र.)

हिंदू धर्म में लाल और पीले रंग से बने कलावे को लेकर कई सारी मान्यताएं प्रचलित हैं जिसे लोग आज भी अपनाते हैं। किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों या शुभ कार्य के समय हाथ में कलावा या मौली बांधने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। शास्त्रों में भी इसे बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। कलावा को रक्षा सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि हाथ में इस रक्षा सूत्र को बांधने से व्यक्ति की हर तरह से रक्षा होती है और उनके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। हालांकि कलावा बांधने और उतारने के कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है। शायद ही लोग इन नियमों के बारे में जानते होंगे। अगर आप भी उनमें से हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको कलावा बांधने और उतारने की विधियों और नियमों के बारे में बताएंगे।

किस दिन उतारना चाहिए कलावा?

ज्योतिष शास्त्र में रक्षा सूत्र यानी कलावा धारण करने और उतारने के कई नियम बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हांथ में बांधा हुआ कलावा सिर्फ मंगलवार और शनिवार के दिन ही खोलना सबसे उत्तम माना गया है। इस खोलने के बाद पूजा घर में ही बैठकर दूसरा कलावा बांध लें।

किस हाथ में कलावा बांधना अधिक शुभ?

ज्योतिष के अनुसार पुरुषों और कुंवारी लड़कियों को दाहिने हाथ में जबकि विवाहित महिलाओं को बांए हाथ में कलावा बांधना चाहिए।

कलावा कैसे बांधा जाता है?

शास्त्रों में कलावा बांधने के कई नियमों के बारे में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस हाथ में आप कलावा बांध रहे हैं उस हाथ में सिक्का या रुपया लेकर मुट्ठी बंद कर लें। उसके बाद दूसरे हाथ को सिर पर रख दें। फिर कलावा बांधने वाले व्यक्ति से 3, 5 या 7 बार कलावा कलाई पर लपेटवाएं। फिर कलावा बंध जाने के बाद हाथ में रखी दक्षिणा उस व्यक्ति को भेंट में दें।

पुराना कलावा का क्या करें?

जब हाथ में बंधा हुआ कलावा पुराना हो जाता है तो इसे इधर-उधर कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए। क्योंकि इस्तेमाल किए गए पुराने कलावा को इधर-उधर फेंकना अशुभ माना गया है। आप हाथ से कलावा निकालकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या फिर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें।

घर की इस दिशा में रखें मटका, हमेशा बनी रहेगी बरकत

वास्तु शास्त्र में घर में रखी जाने वाली हर एक चीज के सही दिशा और नियम निर्धारित किए गए हैं। हर दिशा और हर चीज में अलग ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा पर घर का माहौल निर्धारित होता है। यदि वास्तु शास्त्र के इन नियमों का पालन किया जाए तो घर में सुख-समृद्धि आती है। साथ ही खुशहाली का भी आगमन होता है। यदि इन नियमों की अनदेखी की जाए, तो दरिद्रता आने लगती है। हर व्यक्ति खुशहाल और आरामदायक जीवन जीना चाहता है, इसलिए आज हम आपको घर में रखे जाने वाले मटके से जुड़े कुछ नियम बताने जा रहे हैं।

मटके से जुड़े वास्तु नियम

- वास्तु शास्त्र में धनवान बनने के लिए आसान उपाय बताए गए हैं, जो बहुत प्रभावी हैं। इसके लिए आपको बस एक मिट्टी के मटके की जरूरत होगी।

- वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में मिट्टी का मटका या सुराही होती है, वहां हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। इससे घर में धन का आगमन होता है। घर में बरकत बनी रहती है। पैसों की तंगी दूर होती है। जब भी आप अपने घर में मटका रखें, तो उसमें हमेशा जल भरकर रखें।

- वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा में देवताओं का वास होता है। पानी से भरा हुआ मटका या सुराही हमेशा उत्तर दिशा में रखें। इससे देवी-देवता प्रसन्न होते हैं। घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

- उत्तर दिशा में रखे हुए मटके में हमेशा साफ जल भरकर रखें। इस पानी का उपयोग पीने और भोजन बनाने के लिए करें। यदि मटके के पानी का उपयोग ना करना चाहते हैं, तो इस पानी को पौधों में डाल सकते हैं। ध्यान रहे कि मटके के पानी को समय-समय पर बदलते रहें।

- यदि आप पानी से भरा मटका अपने किचन में रख रहे हैं और उसका उपयोग पीने में करते हैं, तो रोज शाम को तुलसी के पास दिया जलाने के बाद एक दीपक किचन में पीने के पानी के पास भी रख दें। इससे आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी।

पलट जाएगी इन राशि वालों की किस्मत, सूर्य-मंगल की युति से मिलेगा जमकर लाभ

श्री रोशनी शर्मा
9265235662
हस्त रेखा एवं फेस रीडर (ज्योतिषाचार्य)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 17 अगस्त 2023 को सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य एक साल बाद अपनी ही राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन कर अपनी राशि में प्रवेश करना काफी बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। सिंह राशि में ग्रहों के सेनापति मंगल पहले से ही विराजमान हैं। इस तरह सूर्य के गोचर से सिंह राशि में सूर्य और मंगल की युति बनेगी। सूर्य और मंगल की युति का बनना सभी राशियों पर प्रभाव डालने वाला है। वहीं, 3 राशियां ऐसी हैं,

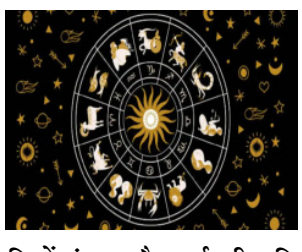

जिन्हें मंगल और सूर्य की युति जमकर लाभ देने वाली है। आइए, जानते हैं कि वे राशियां कौन-सी हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि में ही सूर्य और मंगल की युति बन रही है। इस राशि के जातकों के लिए यह बेहद शुभ है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। आय में वृद्धि होगी। निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। परिवार में किसी बड़े आयोजन के होने से खुशियां आएंगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। अचानक कहीं से पैसा मिल सकता है। वाणी के दम पर काम बनेंगे।

वृश्चिक राशि

सूर्य और मंगल की युति से वृश्चिक राशि वाले जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। आय के नए स्रोत बनेंगे। व्यापारियों को मुनाफा होगा। कारोबार का विस्तार हो सकता है। काफी लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। निवेश से लाभ प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। कोई बड़ी समस्या से छुटकारा मिलेगा। धन लाभ हो सकता है। संतान सुख की प्राप्ति होगी।

मकर राशि

मकर राशि के लोगों को सूर्य और मंगल की युति से काफी लाभ मिलने वाला है। इन लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा। तेजी से काम बनेंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। धन लाभ होगा। नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों के लिए यह समय काफी शुभ है। नई नौकरी के प्रस्ताव आ सकते हैं। जीवन में कोई बड़ा बदलाव होगा। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा।

रास्ते में झाड़ू दिखना शुभ होता है या अशुभ? मिलते हैं ये संकेत

हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है। वास्तु शास्त्र में झाड़ू को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। झाड़ू को इस्तेमाल करने से लेकर उसके रखने तक कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। अगर इन नियमों का पालन न किया जाए, तो मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, झाड़ू घर में साफ-सफाई में उपयोग की जाती है। कहा जाता है कि ये घर में मौजूद नकारात्मकता को दूर करती है। साथ ही सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है। आइए, जानते हैं झाड़ू से जुड़े वे नियम कौन-से हैं, जिनका व्यक्ति को हमेशा पालन करना चाहिए।

रास्ते में झाड़ू दिखना- किसी के आने या जाने के समय झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति घर से निकल जाए और उसे रास्ते में झाड़ू दिख जाए तो यह अशुभ माना जाता है। इस तरह झाड़ू का दिखना अच्छा नहीं माना जाता। इससे व्यक्ति जो भी काम करने जा रहा होता है, उसमें विफलता हासिल हो सकती है।

इस समय लगाएं झाड़ू - सुबह के समय झाड़ू लगाना उत्तम माना जाता है। इस समय घर में झाड़ू लगाने से सुख-समृद्धि का प्रवेश होता है। घर में चार पहर झाड़ू लगाने को सही माना गया है।

इस समय न करें झाड़ू का प्रयोग-शाम के समय घर में झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। ऐसे में आपके घर आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है।

यहां न रखें झाड़ू -कभी भी घर के सामने या बिस्तर के नीचे झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। टूटे झाड़ू को भी घर में नहीं रखना चाहिए। इसे तुरंत बदल देना चाहिए। नए झाड़ू को शुक्रवार के दिन की खरीद कर लाना चाहिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है।

5 साल में 8 लाख लोगों ने छोड़ी भारतीय नागरिकता, इस साल अभी तक 87 हजार

चीन- पाकिस्तान तक को बनाया नया ठिकाना

एजेंसी

साल 2023 अभी करीब आधा हीं गुजरा है और 87 हजार से ज्यादा भारतीय नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में जा बसे हैं। बीते पांच साल के आंकड़े तो बड़ी चिंता की ओर इशारा करते हैं, जिसके दौरान 8 लाख से ज्यादा लोगों ने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। सरकार का कहना है कि ये लोग 'निजी कारणों' के चलते देश की नागरिकता छोड़ रहे हैं। सवाल है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में देशवासी भारत छोड़ रहे हैं और कहां नया ठिकाना बना रहे हैं।

राज्यसभा में उठा सवाल

राज्यसभा में सांसद संदीप कुमार पाठक की ओर से चार सवाल पूछे गए। पहला, बीते पांच सालों में भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले और अन्य देशों की नागरिकता लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है। और देशों की सूची। दूसरा, इनमें से कितने कारोबारी थे। तीसरा, क्या सरकार ने इस बात पर कोई स्टडी की है कि ये लोग देश क्यों छोड़ रहे हैं और अगर हां तो मुख्य वजहें क्या हैं। चौथा, नागरिकता छोड़ने वाले लोगों के पेशे का लेखा जोखा ।

2022 में 2 लाख 25 हजार ने छोडी नागरिकता

सरकार की तरफ से राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने जानकारी दी कि इस साल जून 2023 तक यानी महज 6 महीनों में ही 87 हजार 26 लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। उन्होंने आंकड़े जारी किए कि 2018 में (1 लाख 34 हजार 561), 2019 में (1 लाख 44 हजार 17), 2020 में (85 हजार 256), 2021 में (1 लाख 63 हजार 370), 2022 में (2 लाख 25 हजार 620) लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 2011 में (1 लाख 22 हजार 819), 2012 में (1 लाख 20 हजार 923), 2013 में (1 लाख 31 हजार 405), 2014 में (1 लाख 29 हजार 328), 2015 में (1 लाख 31 हजार 489), 2016 में (1 लाख 41 हजार 603) और 2017 में (1 लाख 33 हजार 49) लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी।

क्यों भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं लोग

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जानकार इसके कई कारण बताते हैं। उनका मानना है कि करियर, जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा के बेहतर मौके, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, साफ हवा जैसे कई कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य कई देशों की तरह भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। ऐसे में विदेशी नागरिकता हासिल करने वाले भारतीयों को औपचारिक रूप से भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। हालांकि, इसके अलावा भी कई वजह गिनाई जाती हैं।

बोईंग ने भारतीय सेना के लिये ई-मॉडल अपाचे का उत्पादन शुरू किया

भारतीय सेना द्वारा ऑर्डर किये गये छह अपाचे हेलिकॉप्टर्स में पहला एएच-64ई के ढांचे हैदराबाद में टाटा बोईंग एरोस्?पेस लिमिटेड के संयंत्र में बन रहे हैं

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

बोईंग मेसा, एरिज़ोना में भारतीय सेना के अपाचे का उत्पादन शुरू कर रही है। कंपनी भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करते हुए कुल छह एएच-64ई अपाचे की आपूर्ति करेगी। इस साल इससे पहले, टाटा बोईंग एरोस्पेस लिमिटेड (टीबीएएल) ने हैदराबाद, भारत में स्थित अपनी आधुनिक फैक्ट्री से भारतीय सेना के पहले एएच-64 अपाचे ढांचे की आपूर्ति की थी। बोईंग इंडिया के प्रेसिडेंट सलिल गुप्ते ने कहा, 'हमें एक और महत्वपूर्ण उपलब्धितक पहुंचने की खुशी है, जिससे भारत की रक्षा क्षमताओं में सहयोग देने के लिये बोईंग की

अटूट प्रतिबद्धता का पता चलता है। एएच-64 की उन्नत टेक्नोलॉजी और साबित प्रदर्शन भारतीय सेना की परिचालन तैयारी को समृद्ध बनाएगा और उसकी रक्षा क्षमताओं को मजबूती देगा।'

2020 में बोईंग ने 22 इंडियन एयर फोर्स ई-मॉडल अपाचे की आपूर्ति पूरी की थी और भारतीय सेना के लिये छह एएच-64ई बनाने के लिये अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे। भारतीय सेना के अपाचे की आपूर्ति 2024 के लिये निर्धारित है। अटैक हेलिकॉप्टर प्रोग्राम्स की वाइस प्रेसिडेंट और बोईंग मेसा साइट की सीनियर एक्जीक्यूटिव क्रिस्टिना उपाह ने कहा, 'एएच'-64ई दुनिया का प्रमुख अटैक हेलिकॉप्टर बना हुआ है। एएच-64 ग्राहकों को बेजोड़ घातकता और उत्तरजीविता क्षमता देता है और हम यह क्षमताएं भारतीय सेना को प्रदान करते हुए रोमांचित हैं।

सुधा मूर्ति बनाएंगी आपके बच्चे का सिलेबस, NCERT ने दी बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली।एजेंसी

देश की जानी-मानी लेखिका और इंफोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति का नाम एनसीईआरटी के पैनल में शामिल किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर स्कूली सिलेबस में संशोधन करने और नया सिलेबस बनाने के लिए गठित की गई ऍंऊ समिति में सुधा का नाम शामिल किया गया है। सुधा मूर्ति के अलावा इस पैनल में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विबेक देबरॉय,सलाहकार समिति के सदस्य संजीव सान्याल, आरएसएस विचारक चामू कृष्ण शास्त्री और सिंगर और म्यूजिक कंपोजर शंकर महादेवन शामिल हैं। NCERT ने बच्चों का सिलेबस बनाने और संसोधन करने के लिए 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण शिक्षण सामग्री समिति (NCTC) गठित की है। इस समिति का अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के चांसलर महेश चंद्र पंत को बनाया गया है। यह समिति देश में स्कूली शिक्षा के लिए सिलेबस और पाठ्यपुस्तक डेवलपर्स के लिए रोडमैप तैयार करेगी। गौरतलब है कि सरकार साल 2024-25 शैक्षणिक सत्र से नई सिलेबस और किताबें लाने के बारे में सोच रही है। ये जिम्मेदारी सरकार ने अब इस समिति को सौंप दी है। कक्षा 3 से 12 तक के लिए स्कूली सिलेबस, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण सामग्री को डेवलप करने ये समिति करेगी।

कौन हैं सुधा मूर्ति

सुधा मूर्ति इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। टाटा की पहली महिला इंजीनियर सुधा मूर्ति जानी-मानी लेखिका और समाजसेवी हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। धीरे से बकुला गिरता है, कैसे मैंने अपनी दादी माँ को पढ़ना सिखाया और अन्य कहानियाँ, महाश्वेता, डॉलर बहू और तीन हजार टांके जैसी कई चर्चित किताबें उन्होंने लिखी है। अपनी बेबाकी के लिए वो चर्चा में रहती है। उनके मोटिवेशनल स्पीच लोगों को खूब पसंद आते हैं। उनके कामों को देखते हुए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

मुंह के बल गिरे टमाटर के भाव, एक दिन में 37 फीसदी लुढ़के, अब 70 रुपये में बेचने की तैयारी

नई दिल्ली। एजेंसी

पिछले दिनों आसमान पर पहुंचे टमाटर के भाव अब नीचे आ रहे हैं। टमाटर की बढ़ती कीमतों (Tomato Price) का असर आम आदमी के बजट पर पड़ा है। लोगों ने टमाटर से दूरी बना ली है। टमाटर इतना महंगा (Tomato Price) हो गया है कि लोगों के लिए 250 ग्राम खरीदना भी मुश्किल हो गया है। दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में टमाटर के भाव 280 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए थे। हालांकि अब इसमें गिरावट आ रही है। सिर्फ एक दिन में ही नासिक की तीन मंडियो में टमाटर की औसत थोक कीमत 650 रुपये प्रति टोकरी तक गिर गई है। बता दें कि एक टोकरी में 20 किलो टमाटर होते हैं। इनके भाव अभी तक 1750 रुपये चल रहे थे। अब यह गिरकर 1100 रुपये पर पहुंच गए हैं। एक दिन में ही इनमें 37 फीसदी की गिरावट आ गई है।धर सरकार ने भी टमाटर की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने की तैयारी कर ली है। दिल्ली-एनसीआर में एनसीसीएफ सस्ती कीमतों पर टमाटर बेचेगी। अगर सरकार की कोशिश कामयाब रही तो इस हफ्ते टमाटर के भाव कम होकर 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकते हैं। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक, सरकार टमाटर की कीमतों को कम करने के लिए नेपाल से टमाटर आयात कर रही है। टमाटर की आवक अब बढ़ गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहां पर सबसे बड़ी टमाटर की मंडी पिंपलगांव में आवक बढ़कर अब 15 हजार डिब्बे हो गई है। पहले यह 1500 डिब्बे थी। इसी तरह से नासिक में यह 5 हजार से बढ़कर 10 हजार डिब्बे, वहीं लासलगांव में यह 1500 डिब्बे पहुंच गई है। यहां पर अभी तक 350 डिब्बों की आवक थी।टमाटर की आवक बढ़ी। टमाटर की आवक बढ़ने से इसके दाम भी गिर गए हैं। पिंपलगांव मंडी में टमाटर की औसत थोक कीमत 1750 रुपये प्रति टोकरी से गिरकर 1200 रुपये प्रति टोकरी पहुंच गई है। यहां पर बीते तीन अगस्त को औसत थोक मूल्य 2400 रुपये प्रति टोकरी दर्ज किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, टमाटर की औसत कीमत जल्द ही एक हजार रुपये प्रति टोकरी से नीचे आने की उम्मीद है। टमाटर की प्रति दिन आवक बढ़कर 25 हजार हो जाएगी।

सभी शहरों में कम होंगे दाम

टमाटर के भाव जल्द ही सभी शहरों में कम हो सकते हैं। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बताया कि सरकार ने टमाटर की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए नेपाल से टमाटर आयात करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार तक वाराणसी और कानपुर में नेपाल से मंगाए गए टमाटर की पहली खेप पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) इस हफ्ते के आखिरी में दिल्ली-NCR में 70 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर टमाटर की एक बड़ी बिक्री की योजना बना रहा है। वित्तमंत्री ने कहा कि एनसीसीएफ ने अभी तक राजस्थान, दिल्ली-ऍंऊ और उत्तर प्रदेश में करीब 8,84,612 किलोग्राम टमाटर बेचे हैं। यह आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा और इसे बढ़ाया भी जाएगा।

टमाटर की कीमत थोक मंडियो में 100 रूपये से नीचे आईं

वित्त मंत्री के मुताबिक, एनसीसीएफ और एनएएफईडी जैसी सहकारी समितियों के जरिए बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में टमाटर बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंध्रप्रदेश और कर्नाटक की थोक मंडियों में टमाटर की कीमतें 100 रुपये के नीचे आने लगी है। बता दें कि सरकार ने टमाटर की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए 14 जुलाई से कदम उठाए थे।

इंदौर स्थित स्टार्टअप एवं टेक कंपनियाँ को लंदन में स्थापित करने का अवसर

लंदन एंड पार्टनर्स कंपनी कर रही मदद, सेमिनार में शामिल हुई 60 कंपिनयां

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

लंदन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार करने की इच्छुक भारतीय कंपनियों के लिए भारत से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए यूरोप में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और विश्व में दूसरा सबसे लोकप्रिय शहर है। यूके में पिछले पाँच सालों से भारत दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है और पिछले दो सालों से लगातार सबसे बड़ा निवेशक बना हुआ है। यूके में 900 से ज्यादा भारतीय कंपनियाँ काम कर रही हैं, और इनमें से आधी से ज्यादा कंपनियों का मुख्यालय लंदन में है।

निवेश के लिए लंदन की ओर बढ़ती रुचि के बारे में हेमिन भरुचा, कंट्री डायरेक्टर, लंदन एंड पार्टनर्स (एलएंडपी) इंडिया ने कहा, लंदन में कार्य के वीज़ा की अवधि बढ़ाकर दो साल किए जाने और इनोवेशन में हुई इस अप्रत्याशित वृद्धि से अंतरराष्ट्रीय उद्यमशीलता के परिवेश में परिवर्तन आ रहा है। इंदौर में आयोजित सेमिनार में 60 से अधिक कंपिनयों ने भाग लिया और निवेश में रूचि दिखाई। उन्होनें कहा कि इंदौर में ज़मीन में निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बेहतरीन अवसर हैं। इस शहर की क्षमता, खास़कर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, लंदन का ध्यान आकर्षित कर रही है। इसके अलावा, एलएंडपी के सहयोग से, लंदन में भारतीय स्टार्टअप यूरोपीय बाजारों का गेटवे बनकर मुख्य वैश्विक बाजारों की पहुंच प्राप्त कर सकते हैं।'

श्री भरुचा ने बताया कि लंदन के मेयर के लिए आधिकारिक प्रतिनिधि संस्था, लंदन एंड पार्टनर्स विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कंपनियों को लंदन में आधार स्थापित करने में मदद कर रही है। मेयर इंटरनेशनल प्रोग्राम छोटे स्टार्टअप्स को लंदन में अपना व्यवसाय स्थापित करने का प्रशिक्षण प्रदान करता है। लंदन भारतीय कंपनियों को विस्तृत ग्राहक आधार है, वैश्विक प्रतिभा, वेंचर कैपिटल फंडिंग और वैश्विक बाजारों से नजदीक, अकाउंटिंग एवं कानूनी व्यवस्था है, तथा सुविधाजनक टाईम ज़ोन के लिए आकर्षित करता है। भारत सरकार इन दोनों देशों में बीच प्रवास सक्रियता से संभव बनाती है, और इस प्रयास में मदद करने के लिए बड़े उपाय करती है।

श्री भरुचा ने कहा, लंदन में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस भारतीय कंपनियों के लिए बहुत अनुकूल है – यहाँ व्यापार की आम भाषा इंगलिश है, और इंगलिश क़ानूनी संरचना का पालन होता है। इसके अलावा, लंदन की अनुकूल परिस्थितियों में आप कई टाइम ज़ोंस में एक ही दिन में एशियन और उत्तर अमेरिकन बाजारों में व्यापार कर सकते हैं।' लंदन एंड पार्टनर्स (एलएंडपी) व्यापार बढ़ाने के लिये अनेक ज़रूरी सेवाएं प्रदान करता है। यह मीटिंग्स के आयोजन, ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराने, बैंक खाते खुलवाने, और नियुक्ति की प्रक्रियाओं में मदद करता है।

इसका श्रेय श्री राजेश अग्रवाल, मेयर ऑफ़ लंदन फॉर बिज़नेस एवं चेयरमैन, लंदन एंड पार्टनर्स को जाता है। इंदौर में जन्मे और पिछले 18 सालों से लंदन में स्थित श्री राजेश अग्रवाल पिछले सात वर्षों तक डिप्टी मेयर रह चुके हैं। वो इंदौर के उद्यमशीलता के जोश और लंदन की वैश्विक पहुंच के सुगम समागम के प्रणेता हैं। लंदन एंड पार्टनर्स (एलएंडपी) सरकारी संरक्षण में स्टार्टअप्स को महत्वपूर्ण सेवाएं बिना किसी शुल्क के प्रदान करता है। यह संगठन छोटे स्टार्टअप का सहयोग कर उन्हें लंदन में स्थापित होने की जटिल प्रक्रिया में उनका मार्गदर्शन करता है।

इंदौर में तीव्र शहरी विकास का टेक्नोलॉजी, रचनात्मक उद्योगों, लाइफ साइंसेज़ और सस्टेनेबिलिटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में लंदन एंड पार्टनर्स के सहयोग के साथ सुगम तालमेल है। लंदन और इंदौर मिलकर एक इनोवेशन पर आधारित भविष्य की नींव रख रहे हैं, जो स्टार्टअप्स को हर महाद्वीप में पहुँचकर वैश्विक सफलता की ओर ले जा रहा है। लंदन की लगभग 6इ आबादी भारतीय मूल की है, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान की गहराई प्रदर्शित होती है।

फ्लिपकार्ट की सेल इवेंट क्राफ्टेड बाय भारत के पांचवें संस्करण का आयोजन

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत के घरेलू ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट समर्थ पहल के तहत अपने महात्वाकांक्षी सेल इवेंट क्राफ्टेड बाय भारत के पांचवें संस्करण की घोषणा की। इवेंट में हस्तशिल्प एवं हथकरघा के क्षेत्र में भारत की समृद्ध विरासत की झलक दिखेगी जिसमें देशभर से कला के 300 से ज्यादा स्वरूपों के एक लाख से ज्यादा उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 15 अगस्त, 2023 से शुरू हुई।

क्राफ्टेड बाय भारत के पांचवें संस्करण को लेकर फ्लिपकार्ट ग्रुप के चीफ कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफिसर रजनीश कुमार ने कहा फ्लिपकार्ट समर्थ पहल और महत्वाकांक्षी सेल इवेंट क्राफ्टेड बाय भारत का सफर उल्लेखनीय रहा है। देशभर के वंचित समुदायों को डिजिटल मार्केट से जोड़ते हुए इनके प्रयासों से 15 लाख से ज्यादा आजीविकाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालना संभव हुआ है। पांचवें संस्करण के साथ हम स्थानीय कारीगरों बुनकरों, हस्तशिल्पियों, स्वयं सहायता समूहों और एमएसएमई समुदायों के विकास को गति देने के मिशन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहे हैं। इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्राफ्टेड बाय भारत सेल इवेंट को विशेष रूप से तैयार किया गया है जहां ग्राहकों को विभिन्न क्षेत्रों की गहरी सांस्कृतिक गाथा और हस्तशिल्प को दर्शाते उत्पादों में से चुनने का मौका मिलेगा जिनसे विरासत की झलक दिखती है प्लेटफॉर्म पर हमारे 45 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को भारत की समृद्ध संस्कृति एवं इतिहास को प्रदर्शित करने वाले इन उत्पादों को खरीदने का मौका मिलेगा।

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाते हुए इस इवेंट में डोकरा, तांत और कलमकारी जैसी विविध कलाओं को प्रदर्शित किया जाएगा, जो राजस्थान और आंध्र प्रदेश की प्राचीन शिल्प परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। फ्लिपकार्ट समर्थ प्रोग्राम से जुड़े लाखों कारीगरों, बुनकरों, दिव्यांगों, स्वयं सहायता समूहों एवं सरकारी एम्पोरियम से जुड़ी महिलाओं को इस इवेंट का हिस्सा बनाया गया है, जो स्वदेश निर्मित हस्तशिल्प एवं सांस्कृतिक उत्पाद प्रस्तुत करेंगे। इनमें जयपुर, सीकर, वाराणसी और विजयवाड़ा जैसे टियर-2 एवं टियर-3 शहर, कुछ शहरी केंद्र और देश के ग्रामीण हिस्सों के लोग शामिल हैं। यह इवेंट फ्लिपकार्ट समर्थ कारीगरों, बुनकरों व हस्तशिल्पियों के साथ जुड़ने और उन्हें देशभर के 45 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच उपलब्ध कराने के फ्लिपकार्ट के सतत प्रयासों का ही हिस्सा है।

ग्रासिम की वृद्धि यात्रा के अगले चरण का काम जारी

पहली तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की। प्रमुख सहायक कंपनियों अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिड़ला कैपिटल और आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स के मजबूत प्रदर्शन से कंसोलिडेटेड (समेकित) राजस्व सालाना 11% बढ़कर रु. 31,065 करोड़ हो गया है। कास्टिक सोडा की कम मांग और आपूर्ति की अधिकता के कारण वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में अंतरराष्ट्रीय कास्टिक सोडा की औसत त्रैमासिक स्पॉट कीमत (सीएफआर एसईए) तिमाही दर तिमाही 20% और सालाना 46% की गिरावट के साथ $415/टन हो गईं। विशेष उत्पादों की अधिक हिस्सेदारी के कारण, स्पेशिलिटी केमिकल्स (एपॉक्सी पॉलिमर और क्योरिंग एजेंट) बिजनेस मार्जिन में तिमाही दर तिमाही और साल दर साल आधार पर सुधार हुआ। स्पेशलिटी केमिकल्स का राजस्व योगदान पिछली तिमाही के समान 25इ रहा। कास्टिक रियलाइजेशन में गिरावट के कारण केमिकल बिजनेस का राजस्व तिमाही दर तिमाही 10% और साल दर साल 21% कम होकर रु. 2,146 करोड़ हो गया। ईबीआईटीडीए तिमाही दर तिमाही 3% और साल दर साल 56% की गिरावट के साथ ?358 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही में लॉन्च होने वाले कामर्शियल सेट ' गो टू मार्केट' की ब्रांडिंग और मार्केटिंग जारी है। प्लांट का निर्माण और इससे संबंधित बुनियादी ढांचा इसी लॉन्च पर आधारित है। ग्रासिम को इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस वर्ल्ड की 2022-23 के लिए भारत की सर्वाधिक सस्टेनेबल कंपनियों की सूची में जगह दी गई थी। अल्ट्राटेक का विस्तार कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। अल्ट्राटेक ने इस तिमाही के दौरान 22MW WHRS क्षमता जोड़ी है। इसके साथ कुल WHRS क्षमता बढ़कर 232MW हो गई है।

आर्थिक मंदी से हांफ रहा ड्रैगन, बेरोजगारी का डेटा रिलीज करने पर भी चीन ने लगाई पाबंदी

जून में एक सर्वेक्षण में युवाओं में बेरोजगारी 21.3 प्रतिशत पाई

एजेंसी।

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करने वाले चीन ने व्यापक आर्थिक मंदी के बीच युवा बेरोजगारी पर मासिक डेटा जारी करने पर रोक लगा दिया है। चीन की सरकार की तरफ से ऐसा तब किया गया है, जब देश में युवा बेरोजगारी की दर ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। यह निलंबन चीन की युवा बेरोजगारी दर के हाल के महीनों में लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आया है। अप्रैल से जून तक 16 से 24 साल के बच्चों के लिए बेरोजगारी दर क्रमशः 20.4इ 20.8इ और 21.3इ तक पहुंच गई। इस खबर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है और लोग चीन की सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी से पैदा हुए आर्थिक नुकसान से चीन अब तक रिकवर नहीं कर पाया है। इस बीच, मंगलवार को आधिकारिक डेटा में बताया गया है कि जुलाई में चीन में आर्थिक मंदी गहरा गई है। मंदी के बीच चीन के केंद्रीय बैंक ने अप्रत्याशित रूप से प्रमुख ब्याज दर में कटौती की है। जून में एक सर्वेक्षण में 16 वर्ष से 24 वर्ष तक की आयु के शहरी कामगार युवाओं में बेरोजगारी 21.3 प्रतिशत पाई गई और आबादी का यह हिस्सा महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने पर काम नहीं पा सका। इससे पहले, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (एनबीएस) ने हर महीने 16 से 24 साल के बच्चों के लिए शहरी बेरोजगारी दर का खुलासा किया था। एनबीएस के प्रवक्ता फू लिंगहुई ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मौजूदा आंकड़ों में 'सुधार की जरूरत है।' जून में एक सर्वेक्षण में 16 वर्ष से 24 वर्ष तक की आयु के शहरी कामगार युवाओं में बेरोजगारी 21.3 प्रतिशत पाई गई थी। आबादी का यह हिस्सा कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के बावजूद काम नहीं पा सका है।

हालांकि, आयु वर्ग के आधार पर बेरोजगारी दर का प्रकाशन संदिग्ध है, जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो इस पर विचार कर रहा है कि वह डेटा का मापन कैसे करे। ब्यूरो के प्रवक्ता फु लिंघुई ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि शहरी कामगारों के बीच संपूर्ण बेरोजगारी 5.3 प्रतिशत है, जो जून से 0.1 प्रतिशत तक अधिक है। फु ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'बेरोजगारी की स्थिति आमतौर पर स्थिर है।' फु के मुताबिक, उपभोक्ता व्यय में वृद्धि एक साल पहले के जुलाई महीने की तुलना में, पिछले महीने 3.1 प्रतिशत से घटकर 2.5 प्रतिशत रह गई है। मंगलवार को जारी हुए आंकड़े के मुताबिक, फैक्टरी उत्पादन में वृद्धि 4.4 प्रतिशत से घटकर 3.7 प्रतिशत रह गई है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए अमेरिका, यूरोपीय केंद्रीय बैंकों के ब्याज दर घटाने के बाद निर्यात मांग घटने पर ऐसा हुआ। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने बैंकों को एक सप्ताह के ऋण पर ब्याज दर 1.9 प्रतिशत से घटाकर 1.8 प्रतिशत कर दिया है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।